भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 551

उत्तर देने की तारीख- 06/02/2023

जनजातीय बच्चों को उनके मूल परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

551. श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातीय बच्चों को उनके मूल परिवेश में उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश के जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने की कोई योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित देश में आज तक कुल कितने ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं और कितने कार्य कर रहे हैं; और

(घ) क्या उक्त योजना के लिए जनसंख्या संबंधी कोई मानदंड हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (घ): सरकार ने अनुसूचित जनजाति की 50% या उससे अधिक और कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों (2011 की जनगणना के अनुसार) की आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई गई हो, ताकि जनजातीय छात्रों को अपने मूल वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर के जनजातीय क्षेत्रों में 740 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ईएमआरएस, पहले 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' के तहत एक घटक था। अप्रैल 2019 में, ईएमआरएस के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक पृथक योजना तैयार की गई थी और ईएमआरएस की योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) बनाया गया था। 31 जनवरी, 2023 तक, कुल 690 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 401 ईएमआरएस के कार्यशील होने की सूचना है। ईएमआरएस की स्थापना के मौजूदा मानदंडों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में किसी भी ब्लॉक को चिन्हित नहीं किया गया है।

*****